भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न संख्या : 266
गुरुवार, 7 अगस्त, 2025/16 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विंग्स इंडिया 2026

***266. श्री जनार्दन मिश्रा:**
श्री सतीश कुमार गौतम:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विंग्स इंडिया 2026 के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या विंग्स इंडिया 2026 के अंतर्गत 'एडवांस्ड एयर मोबिलिटी' (एएएम) से संबंधित परियोजनाओं को कोई नियामक मंजूरी, वित्तीय सहायता या प्रायोगिक परियोजना संबंधी सुविधा प्राप्त हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सहायता के स्वरूप, कार्यान्वयन एजेंसियों और लक्षित क्षेत्रों या चिकित्सा संबंधी संभार तंत्र, आपदा पर प्रतिक्रिया या अंतिम-मील तक संपर्क जैसे उपयोग-मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ओडिशा सहित विभिन्न राज्यों को राष्ट्रीय विमानन विकास कार्यनीति में समाहित करने हेतु प्रस्तावित पहलों, साझेदारियों या निवेश योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"विंग्स इंडिया 2026" के संबंध में श्री जनार्दन मिश्रा और श्री सतीश कुमार गौतम द्वारा पूछे गए दिनांक 07 अगस्त, 2025 के लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या 266 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): विंग्स इंडिया 2026 एशिया का सबसे बड़ा नागर विमानन कार्यक्रम है जो प्रदर्शनियों और उच्च-स्तरीय संवादों के माध्यम से वैश्विक हितधारकों को जोड़ता है। इस आयोजन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

i) भारत के नागर विमानन के विकास और विमानन पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करना।

ii) वैश्विक एयरलाइनों, मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम), अवसंरचना प्रदाताओं, निवेशकों और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दिग्गजों के बीच सहयोग को सुगम बनाना।

iii) सुरक्षा, स्थिरता, उन्नत एअर मोबिलिटी और डिजिटल विमानन में नवाचार को बढ़ावा देना।

iv) सरकार से सरकार (जी2जी)/व्यवसाय से व्यवसाय (बी2बी)/व्यवसाय से सरकार (बी2जी) के बीच बैठकों, गोलमेज सम्मेलनों और पैनल चर्चाओं के माध्यम से साझेदारी को सक्षम बनाना।

v) घरेलू क्षमताओं को उजागर करके मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहलों में सहयोग करना।

vi) सम्मेलनों, तकनीकी सत्रों और युवाओं के साथ संपर्क के माध्यम से ज्ञान साझाकरण और विकास को बढ़ावा देना।

(ख) और (ग): विंग्स इंडिया, विमानन उद्योग और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जो उन्नत एअर मोबिलिटी (एएएम) सहित नागर विमानन क्षेत्र के लिए विचारों के आदान-प्रदान और पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर केंद्रित है। इस आयोजन के दौरान समर्पित सत्रों, नीतिगत गोलमेज बैठकों और प्रदर्शन के अवसरों के माध्यम से एएएम परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाता है।

उन्नत एअर मोबिलिटी (एएएम) हवाई परिवहन में एक नई तकनीक के रूप में वैश्विक स्तर पर उभरता हुआ क्षेत्र है। नागर विमानन मंत्रालय, भारत में एएएम की क्षमता का पता लगाने के लिए हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहा है। विंग्स इंडिया 2026 की भविष्य के विनियामक और परियोजना विकास ढाँचों का समर्थन करने के उद्देश्य से संवाद को सुविधाजनक बनाने, जागरूकता बढ़ाने और आगामी एएएम प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने हेतु एक मंच के रूप में परिकल्पना की गई है। चिकित्सा रसद, आपदा प्रतिक्रिया और अंतिम-मील कनेक्टिविटी सहित संभाव्य उपयोग-मामलों की पहचान करने के लिए ओईएम, राज्य सरकारों, विनियामक प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों के साथ सुसंगत सम्पर्क किए जा रहे हैं।

(घ): टियर-2 और टियर-3 शहरों में असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों का विकास करके क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई उड़ान योजना, राष्ट्रीय विमानन विकास रणनीति में राज्य सरकारों को सक्रिय रूप से शामिल करती है। हवाईअड्डों और हवाईपट्टियों की

पहचान संबंधित राज्यों के परामर्श से की जाती है, जो विभिन्न प्रोत्साहनों जैसे निशुल्क भूमि, विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर कम वैट, और सुरक्षा और अग्निशमन जैसी अवसंरचना और सेवाओं के लिए लागत-साझाकरण के माध्यम से विकास और सहायता के लिए सहमति भी प्रदान करते हैं। राज्य ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के लिए भूमि अधिग्रहण और मौजूदा हवाईअड्डा अवसंरचना के विस्तार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारत के विमानन क्षेत्र का सफल विकास काफी हद तक केंद्र सरकार और ओडिशा सहित विभिन्न राज्यों के सहयोगात्मक प्रयासों पर निर्भर करता है। जहाँ केंद्र सरकार, राष्ट्रीय विजन और नीतियाँ निर्धारित करती है, वहीं राज्य, आवश्यक भूमि और अवसंरचना सहायता प्रदान करके, हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके और एयरलाइनों तथा विमानन-संबंधित व्यवसायों के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर उन नीतियों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

******